वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
मंत्रिमंडल के लिए अप्रैल, 2023 माह हेतु डीपीई की मासिक उपलब्धियां

1. **कैपेक्स लक्ष्य:**

   i. अप्रैल, 2023 माह तक के चुनिंदा सीपीएसईज़ (100 करोड़ रूपये और उससे अधिक के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य के साथ) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य 7,33,345 करोड़ रूपये (बजट अनुमान) और उसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 04 मई, 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 30.04.2023 तक 7.33 लाख करोड़ रुपये (लगभग) के अनुमानित व्यय की तुलना में, उपलब्धि 0.54 लाख करोड़ रुपये (लगभग) अर्थात लगभग 7.39% है।

   ii. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 5.75 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजीगत व्यय की तुलना में, उपलब्धि 5.91 लाख करोड़ रुपये अर्थात अनुमान का 102.71% थी । जबकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, 6.46 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजीगत व्यय की तुलना में, उपलब्धि 6.49 लाख करोड़ रुपये अर्थात अनुमान का 100.53% है।

2. **सीपीएसईज़ का संचालन:**

   i. कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति ने 06.04.2023 को रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

   ii. 7 नवसृजित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के लिए 250 करोड़ रुपये तक का पूंजीगत व्यय करने के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई और रक्षा मंत्रालय को सिफारिश की गई।

   iii. भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण (एएआई) में हवाई यातायात नियंत्रकों के बोर्ड स्तर से नीचे के 456 पदों के सृजन के लिए नागर विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

   iv. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) में ई-7 में महाप्रबंधक के बोर्ड स्तर से नीचे के एक पद के सृजन के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

   v. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के बोर्ड में निदेशक (मानव संसाधन) के एक पद के सृजन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

   vi. 'विवाद से विश्वास I – एमएसईज़ के लिए राहतः संशोधित आदेश' पर व्यय विभाग के दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2023-पीपीडी में निहित अनुदेशों को सूचना और अनुपालन के लिए सभी सीपीएसईज़ को दोहराया गया था।

   vii. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) में गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) का एक पद इस माह के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विभाग द्वारा भरा गया है।

3. **वेतन संशोधन और वेतन अधिसूचना:**

   i. डीपीई ने 2017, 2007, 1997 और 1992 और 1987 आईडीए वेतनमानों के लिए दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 13.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डीए आदेश जारी किए हैं। डीपीई ने सीपीएसईज़ कर्मचारियों के लिए 6 वें और 7 वें सीपीसी के मामलों में सीडीए पैटर्न वेतनमान के संबंध में डीए आदेश भी जारी किए हैं।

   ii. डीपीई ने आईडीए पैटर्न वेतनमानों का पालन करने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि की गणना के संबंध में दिनांक 26.04.2023 को एक स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0029/2021-डीपीई (डब्ल्यूसी) जारी किया है। इससे वीआरएस के माध्यम से 01.10.2020 और 30.06.2021 के बीच सेवानिवृत्त होने वालों को राहत मिलेगी।

4. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):**

   i. अप्रैल-जनवरी 2022-23 की अवधि के लिए शीर्ष 25 कंपनियों का सीएसआर व्यय 1930 करोड़ रुपये था।

   ii. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, डीपीई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए सामान्य विषय के रूप में 'स्वास्थ्य और पोषण' को अधिसूचित किया।

5. **सीपीएसईज़ का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन:**

   इस महीने के दौरान नांगल, नैनीताल और श्रीनगर में आउटरीच बैठकों में इस विषय पर मंत्रालयों/सीपीएसईज़ के साथ परामर्श किया गया था। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 दोनों के लिए समझौता ज्ञापन जारी किए जाएंगे। मसौदा समझौता ज्ञापन के लिए आधार टेम्पलेट और बेंचमार्किंग पद्धति तय की गई है। तदनुसार, समझौता ज्ञापनों का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

6. **अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल नोट्स:**

i. अप्रैल, 2023 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में विनिवेश/पूंजी प्रबंधन और लाभांश के लिए सचिवों के अंतर-मंत्रालयी समूह/कोर समूह की 04 बैठकें आयोजित की गई।

ii. डीपीई ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित निम्नलिखित नोटों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं:

क. झरिया मास्टर प्लान के लिए आगे की राह पर समिति की रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा वितरित मसौदा कैबिनेट नोट।

ख. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रमुख पत्तनों द्वारा भूमि उपयोग प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, 2023 पर मसौदा कैबिनेट नोट।

7. सीपीएसईज़ द्वारा जीईएम और एमएसएमई के माध्यम से खरीद:

i. हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव ने जीईएम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद में कई गुना वृद्धि सुनिश्चित की, जो 2020-21 में 7,027 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 45,958 करोड़ रुपये हो गई। जो वर्ष 2022-23 के दौरान बढ़कर 1,05,780 करोड़ रुपये हो गया है।

ii. एमएसई के लिए सरकार द्वारा घोषित समर्थन उपायों के अनुरूप, वर्ष 2021-22 के दौरान एमएसई से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद अनिवार्य 25% की तुलना में लगभग 32% थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 35% हो गई है।

8. मिशन भर्ती:

i. सीपीएसईज़ में मिशन भर्ती के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को सीपीएसईज़ के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

ii. डीपीई डीओपीटी के 'मिशन भर्ती' पोर्टल पर अपेक्षित जानकारी अपलोड करने के लिए सीपीएसई के साथ नियमित समीक्षा करता है। सीपीएसईज़ ने दिनांक 16 मई, 2023 को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की 5 वीं श्रृंखला के लिए 2096 नई नियुक्तियों का योगदान दिया है। सीपीएसईज़ से संचयी योगदान अब तक 21,299 नियुक्तियां रही हैं।

9. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

अप्रैल, 2023 तक एएमआरसीडी तंत्र के तहत कुल 135 मामलों की सूचना मिली है, जिनमें से 41 मामलों का निपटारा किया गया है (29 मामलों को एएमआरसीडी द्वारा निपटाया गया था और 12 मामलों को या तो एएमआरसीडी के बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया गया था या दो बार रिपोर्ट किया गया था)। अब तक, सीपीएसईज़ के बीच या सीपीएसईज़ और केंद्र सरकार के विभागों/संगठनों से संबंधित 72 मामले लंबित हैं। इसके अलावा, सीपीएसईज़ और राज्य सरकारों/विभागों/संगठनों के बीच 22 मामले भी लंबित हैं।

10. आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम:

आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसईज़ के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए (i) नांगल (पंजाब), (ii) श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और (iii) नैनीताल (उत्तराखंड) में डिजिटल एमओयू डैशबोर्ड के माध्यम से सीपीएसईज़ के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पर आउट-रीच कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

******